

क्या बंगाल में भाजपा का “ट्रंप कार्ड” साबित होंगे नए अध्यक्ष नितिन नबीन

बंगाल में भाजपा ने “भद्रलोक” (जिसमें कायस्थ अधिक हैं) वोटर्स को साधने की रणनीति बनाई है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पश्चिम बंगाल में एक “ट्रम्प कार्ड” के रूप में उभरेंगे, जहाँ कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं।

बिहार चुनावों के सबक पश्चिम बंगाल में भाजपा के काम नहीं आयेंगे। बिहार में एनडीए ने महागठबंधन के खिलाफ 0.1 प्रतिशत वोट शेयर के अंतर के साथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी, जबकि पश्चिम बंगाल में 2021 के पिछले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का वोट शेयर 10 प्रतिशत अधिक था। बिहार में भाजपा की सफलता में छोटे दलों, जिनमें एलजेपी (आरबी) शामिल है, के साथ गठबंधन का बड़ा योगदान था, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वहाँ

- बंगाल में हालांकि भद्रलोक के वोटर्स की संख्या कम है पर वे आम वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। बंगाल की कई नामचीन हस्तियां इसी वर्ग से आती हैं, जैसे, स्वामी विवेकानन्द, अरबिंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चितरंजन दास, ज्योति बसु, सत्यजित रे, बिमल मित्र आदि।
- बिहार में भाजपा के गठबंधन एनडीए और विपक्ष के महागठबंधन में मात्र 0.1 प्रतिशत का वोट अंतर था पर बंगाल में तृणमूल का वोट शेयर भाजपा से 10 प्रतिशत अधिक है। बिहार के विपरीत यहां भाजपा को छोटे-छोटे दलों का सहारा भी नहीं है।
- सवाल यह है कि क्या भद्रलोक को साधकर भाजपा तृणमूल के आसपास पहुंच पाएगी?

केवल वामपंथी और कांग्रेस ही अन्य प्रमुख दल हैं, तथा स्वतंत्र उम्मीदवार के भी छोटी-मोटी संख्या में ही चुनावी मैदान में उतरने की उम्मीद है। ममता

बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की महिला वोटर्स पर काफी मजबूत पकड़ है। तो, भाजपा इन चुनौतियों से कैसे काबू पायेगी।

जाहिर है, भाजपा का सबसे अच्छा विकल्प, टीएमसी के साथ ही, वामपंथी और कांग्रेस के मूल समर्थन आधार को साधना है और उन ‘भद्रलोक’ वोटर्स की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करना है, जो संख्या में कम होते हुए भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यही वह जगह है, जहाँ नबीन, जो कि कायस्थ जाति से हैं, की महत्वपूर्ण भूमिका की उम्मीद है।

बंगाल के कायस्थ, जो शिक्षित और प्रभावशाली हैं, अपनी प्राचीन परंपरा पर गर्व करते हैं। जाने-माने बंगाली कायस्थों में स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ज्योति बसु, चितरंजन दास, सत्यजीत रे, बिमल मित्र, जैमिनी राय, अमर्य सेन और सर जदुनाथ सरकार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि नये कार्यकारी अध्यक्ष, अपने जमीनी दृष्टिकोण के साथ, इस वर्ग (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऐथनॉल ब्लैंडिंग की सफलता के बीच गडकरी फिर विवादों में

उनके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप है कि ऐथनॉल ब्लैंडिंग कार्यक्रम में उन्होंने अपने बेटों को व्यवसायिक लाभ पहुंचाया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भारत की 20 प्रतिशत ऐथेनॉल मिश्रण नीति (ई 20) को लेकर एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। यह विवाद मुख्य रूप से हितां के टकराव के आरोपों, वाहनों के प्रदर्शन से जुड़ी चिंताओं और राजनीतिक विरोध पर केंद्रित है।

उन पर लगाए गए प्रमुख आरोपों में सबसे अहम हितां के टकराव का है। सितंबर 2025 में कांग्रेस पार्टी और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नितिन गडकरी ने सरकारी नीति का इस्तेमाल अपने परिवार के व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए किया।

आरोपों के अनुसार, उनके बेटे निखिल गडकरी द्वारा संचालित सियान एग्रो इंडस्ट्रीज की आयवित्तवर्ष 2024

- एक विवाद यह भी है कि ऐथेनॉल युक्त पेट्रोल-डीज़ल से वाहनों के इंजन खराब हो रहे हैं और वाहनों का माइलेज भी घट गया है।
 - लेकिन नितिन गडकरी इन सभी आरोपों से इनकार करते हैं, उनका कहना है कि पेट्रोल लॉबी पैसे देकर उनके खिलाफ यह दुष्प्रचार करवा रही है।
- की पहली तिमाही में 17.47 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 510 करोड़ रुपये से अधिक हो गई।
- इसी तरह, उनके दूसरे बेटे सारंग गडकरी द्वारा संचालित मानस एगो इंडस्ट्रीज भी ऐथेनॉल सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) की एक बड़ी कंपनी बताई जाती है। आलोचकों का कहना है कि ई20 ईंधन को पूरे देश में तेजी से लागू किए जाने के कारण इन कंपनियों को असाधारण मुनाफा हुआ।
- वाहनों के प्रदर्शन को लेकर भी

वनरक्षक पेपर लीक में लेखाकार व वनरक्षक गिरफ्तार

जयपुर, 22 दिसंबर। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी)ने वनरक्षक भर्ती-2020 परीक्षा के पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, पेपर पढ़ने वाले लेखाकार सहित वनरक्षक को गिरफ्तार किया है। अब जाकर एसओजी की जांच में खुलासा हुआ है कि उदयपुर व बांसवाड़ा के अलावा जयपुर में भी वनरक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ

- एसओजी ने अपने घर पर लीक पेपर पढ़वाने वाले वनरक्षक तथा लीक पेपर पढ़कर वनरक्षक की नौकरी हासिल करने वाले को गिरफ्तार किया।

था। जयपुर में एक लेखाकार ने अपने घर पर वनरक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को लीक पेपर पढ़वाया था। इसके बाद एसओजी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए आरोपी लेखाकार सहित, लीक पेपर पढ़कर परीक्षा पास करने और नौकरी हासिल करने वाले वनरक्षक को पकड़ा है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी साले-बहनोई हैं।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि वनरक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के पिछले दिनों गिरफ्तार मुख्य आरोपी जबराम से पूछताछ में पता चला कि टोडाभीम निवासी लेखाकार अमन जोरवाल ने जयपुर में अपने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

घोषणा के साथ ही झटका लगा भारत न्यूजीलैंड ट्रेड डील को

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे “बैड डील” करार दिया

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 22 दिसंबर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा बड़े जोर-शोर से घोषित मुक्त व्यापार समझौते (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट – एफटीए) को एक उस समय एक तगड़ा झटका लगा, जब सत्ताधारी गठबंधन के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे “खराब समझौता” करार देते हुए कहा कि यह “बहुत अधिक देने” तथा “बहुत कम” प्राप्त करने वाला समझौता है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस समझौते को स्वीकरण एक टेलीफोन कॉल के दौरान किया, जो द्विपक्षीय, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के एक बड़े विस्तार का संकेत देता है। इस समझौते पर तीन महीनों के भीतर हस्ताक्षर होने की उम्मीद

है और 2026 में यह क्रियान्वित हो जायेगा।

दोनों पक्षों ने इसे ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी बताया, और यह भारत-न्यूजीलैंड एफटीए रिकॉर्ड नौ महीने में पूरा हो गया। इस समझौते की विधिवत बातचीत पीएम लक्सन की मार्च 2025 में भारत यात्रा के दौरान शुरू हुई थी।

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री पीटर्स ने न्यू दिल्ली और वेलिंगटन के बीच हुए इस एफटीए का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व वाली सरकार ने डील में “सबस्टेंस” का ध्यान नहीं रखा और शीघ्र डील होने पर ध्यान रखा।

पीटर्स, जो “न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी” के नेता और सरकार में गठबंधन साझेदार हैं, ने कहा कि उनकी पार्टी “खेद सहित” इस समझौते के खिलाफ

- विंस्टन पीटर्स ने कहा, इसमें न्यूजीलैंड को बहुत कुछ देना पड़ेगा पर बदले में उसे बहुत कम मिलेगा। पीटर्स न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता हैं, जो न्यूजीलैंड की गठबंधन सरकार का हिस्सा है।
- भारत और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने टेलिफोन वार्ता में इस डील की घोषणा की। इस डील पर तीन माह के भीतर हस्ताक्षर होने और इसके 2026 में क्रियान्वित होने की संभावना है।

है और जब यह संसद में पेश होगा तो वे इसके सक्षम कानून का रूप लेने के खिलाफ मतदान करेंगे।

पीटर्स ने एक्स पर लिखा, “हम भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को न तो मुक्त मानते हैं और न ही निष्पक्ष।” उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के आर्थिक और श्रमिक हितों

पीटर्स ने कहा, “प्रति व्यक्ति आधार पर, राष्ट्रीय सरकार ने न्यूजीलैंड के श्रम बाजार में भारत को कहीं अधिक पहुंच दे दी है, जितनी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ने अपने को सुरक्षित करने के लिए नहीं दी थी। यह न्यूजीलैंड के वर्तमान श्रम बाजार की स्थिति को देखते हुए यह बेहद अव्यावहारिक है, जहां बहुत से न्यूजीलैंडवासी बेरोजगारी या आर्थिक रूप से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।”

उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए एक नया रोजगार वीजा सुचित के बारे में भी चिंता जताई।

उन्होंने कहा, खासतौर से भारत के नागरिकों के लिए एक नया रोजगार वीजा बनाने से न्यूजीलैंड में भारतीय आप्रवासन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है जबकि हमारा श्रम बाजार पहले से ही बहुत तंग है।”

मोर का शिकार कर पार्टी करते ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार

उदयपुर, 22 दिसम्बर (कासं)। जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र बिलख फला गडावत गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक रूपलाल पुत्र प्रेमशंकर मीणा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष है तथा दूसरा हिस्ट्रीशीटर अर्जुनलाल पुत्र भगवान मीणा है, तीसरा आरोपी राकेश पुत्र कुरीचंद है। तीनों ही आरोपी एक गांव के हैं।

प्रकरण के अनुसार, रविवार को गश्त के दौरान एसएसआई रमेशचन्द्र को ऋषभदेव थाना क्षेत्र बिलख फला

- श्रृषभदेव थाना पुलिस ने ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल प्रेम शंकर मीणा के साथ एक हिस्ट्रीशीटर अर्जुनलाल मीणा को भी पकड़ा।

गडावत गांव में नदी किनारे किसी जानवर का शिकार कर पार्टी करने के लिए पकाने की सूचना मिली। इस पर टीम मौके पर पहुंची। जहां तीनों आरोपी शिकार किए गये राष्ट्रीय पक्षी मोर को पकाले मिले। तीनों को दबोचकर तथा इनके कब्जे से शिकार किए मोर के अवशेष जब्त कर, पूछताछ के लिए थाने लेकर आए।

वन विभाग अधिकारियों को सूचना देने पर वनरक्षक सुमित्रा ने मौके पर पहुंच आवश्यक कार्यवाही शुरू की। इधर इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘भारत हिंदू राष्ट्र है’

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 22 दिसंबर। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कोलकाता में कहा कि इसके लिए किसी संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सच है।

आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और तब तक रहेगा जब तक देश में भारतीय संस्कृति को महत्व दिया जाता रहेगा।

भागवत ने कोलकाता में आरएसएस के ‘100 व्याख्यान माला’

- संघ प्रमुख भागवत ने यह दावा करते हुए कहा, संविधान में हिंदू राष्ट्र शब्द जुड़े तो ठीक, ना जुड़े तो भी ठीक, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है यह सत्य है।

कार्यक्रम में कहा, सूरज पूर्व दिशा से उगता है। हमें नहीं पता यह कब से हो रहा है। तो क्या इसके लिए भी हमें संविधान को मंजूरी चाहिए? हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। जो भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, वह भारतीय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘आईपीएस पंकज चौधरी के बकाया प्रमोशनों पर प्रोविज़नल तौर पर विचार करें’

जयपुर, 22 दिसंबर। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी को राहत देते हुए राज्य सरकार को कहा है कि वह डीपीसी के तहत उनके बकाया चल रहे प्रमोशन पर प्रोविजनल तौर पर विचार

- केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (कैट) ने राज्य सरकार को निर्देश दिये।

करे। अधिकरण ने यह आदेश पंकज चौधरी के प्रार्थना पत्र पर दिया।

मामले से जुड़े अधिवक्ता अनुपम अग्रवाल ने बताया कि प्रार्थी के खिलाफ चल रहे केसों के कारण तीन प्रमोशन बकाया हैं। इनमें साल 2018 से जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिव और 2021 से सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक के प्रमोशन शामिल हैं। इसके साथ ही साल 2023 से उनका डीआईजी रैंक का प्रमोशन भी रुका हुआ है। राज्य सरकार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऐथनॉल ब्लैंडिंग में 20 प्रतिशत लक्ष्य हासिल, भारत की बड़ी उपलब्धि

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपलब्धि तय समय से 5 साल पहले ही प्राप्त कर ली गई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। भारत को ऐथेनॉल ब्लैंडिंग कार्यक्रम में 20 प्रतिशत की लक्ष्य प्राप्त तय अवधि से पांच साल पहले ही हो गई है, जिससे कच्चे तेल के आयात व्यय में कटीती हुई है और यह सतत ईंधन परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत के प्यूल पंपों पर दशकों की सबसे बड़ी परिवर्तन प्रक्रिया चल रही है। देश का ऐथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम पायलट चरण से राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुका है, जिसमें ऐथनॉल सप्लाई इयर (ईएसवाय) 2024-25 में ब्लैंडिंग औसतन 19.24 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और ईएसवाय 2025-26 में ई 20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत ऐथनॉल का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है।

पिछले पांच वर्षों में, ब्लैंडिंग

- पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीज़ल) से इकोफ्रेंडली ईंधन के इस्तेमाल की तरफ जाने की दिशा में यह बड़ी सफलता है।
- ऐथेनॉल उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे नम्बर पर है वहीं स्थान पर यूएसए तथा दूसरे पर ब्राज़ील है।

8.10 प्रतिशत से बढ़कर ईएसवाय 2020-21 में 14.60 प्रतिशत तक पहुंच गई, जब 707.40 करोड़ लीटर ऐथनॉल पेट्रोल में मिलाया गया। बिल्कुल हाल ही में ईएसवाय (नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक) में, 1,022.4 करोड़ लीटर ऐथनॉल मिलाया गया, जिससे औसतन 19.24 प्रतिशत की ब्लैंडिंग हासिल हुई, जो ई 20 लक्ष्य के बेहद करीब है।

यह जानकारी 8 दिसम्बर 2025 को राज्य सभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी

ऐथेनॉल ब्लैंडिंग भारत को विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) की बचत में भी मदद कर रहा है, क्योंकि यह कच्चे तेल के आयात बिल को कम कर रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 दिसम्बर 2025 को संसद में बताया कि पिछले कुछ वर्षों में ऐथेनॉल ब्लैंडिंग की वजह से देश ने 1,55,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत की है।

इन लाभों के बावजूद, और 2024 में 6.2 बिलियन लीटर ऐथेनॉल का उत्पादन करने के बावजूद, भारत अभी भी वैश्विक नेताओं, अमेरिका और ब्राज़ील से पीछे है, जैसा कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से पता चलता है।

वैश्विक ऐथेनॉल उत्पादन में अमेरिका की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत (61.4 बिलियन लीटर) है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

तुम्हारा बायाँ हाथ जो देता है, उसे दायाँ हाथ ना जानने पाए। –बाइबल

कहीं ‘जी राम जी’ का ‘जय राम जी’ न हो जाये

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून या नरेगा 2005 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बनाया गया। इसके माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रमिकों को साल में 100 दिन काम देने की गारंटी दी गई थी। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार हुआ जब ग्रामीणों को काम मांगने और प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया। स्थानीय पंचायत से काम मांगने के लिए आवेदन देने के 15 दिन के अंदर यह अनिवार्य था कि उसे किसी न किसी काम पर, जो उसके निवास से पांच किलोमीटर से कम दूरी पर हो, उसे काम दिया जाए। काम न दे पाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था, जो देय मजदूरी का एक चौथाई होता था।

वैसे तो स्वतंत्रता के बाद कई प्रकार की योजनाएं बनाई गईं जिनके अंतर्गत ग्रामीणों को काम देने का प्रावधान था, जैसे ‘फूड फॉर वर्क’, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम; , ‘जवाहर रोजगार योजना’ आदि इनके अतिरिक्त अकाल की स्थिति में अकाल राहत कार्य के अंतर्गत भी ग्रामीणों को मजदूरी दी जाती थी। इन सब योजनाओं में काम देने की कोई गारंटी या कानूनी बाध्यता नहीं थी।

आवश्यकता अनुसार मजदूरी को काम पर लगाया जाता था। इस कारण संबंधित कार्यकारी एजेंसी इनमें कई बार मनमानी करती थी और इससे भ्रष्टाचार भी पनपता था। यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीणों के पास मजदूरी का कोई विकल्प नहीं होने के कारण ठेकेदार/नियोक्ता, मजदूरों का आर्थिक शोषण करते थे और बहुत कम मजदूरी पर रखते थे। बंधुआ मजदूरी की प्रथा भी इसी प्रकार की व्यवस्था का परिणाम थी।

। लोग पीड़ी दर पीड़ी जमींदारों के यहां काम करते और उन्हें केवल नाम मात्र का खाना दिया जाता एवं कभी कभार उन्हें किसी कार्य हेतु कुछ राशि दे दी जाती थी।

यूपीए सरकार ने स्थिति की गंभीरता को पहचाना और इसमें क्रांतिकारी बदलाव करते हुए काम के अधिकार की गारंटी ग्रामीणों को दी। इस हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2005 बनाया। 2009 में इसमें महत्वात्मा गांधी का नाम जोड़कर इसे महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है।

नरेगा के प्रारंभिक वर्षों में, राजस्थान के नरेगा आयुक्त के पद पर लगभग सात माह काम करने का अवसर मिला। इस दौरान नरेगा में राजस्थान में, देश में सर्वाधिक रोजगार सृजन हुआ और एक वर्ष में लगभग 6000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने जारी किए। यह कोई केंद्र प्रवृत्ति योजना नहीं थी एवं इसके लिए बजट की कोई सीमा नहीं थी। केवल एक आवश्यकता थी कि जितने लोग रोजगार मांगें उन्हें 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। इस योजना के दिशा निर्देश में यह स्पष्ट लिखा गया था कि वही काम लिए जाएं जिन पर सामग्री खर्च कुल काम के 40 प्रतिशत से अधिक न हो एवं 60 प्रतिशत हिस्सा मजदूरी के रूप में दिया जाए। इस कानून के अंतर्गत भारत सरकार, मजदूरी का शत प्रतिशत एवं सामग्री एवं प्रशासनिक व्यय का 75 प्रतिशत राज्य सरकारों को उपलब्ध कराती थी। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों पर नरेगा के अंतर्गत होने वाले कुल व्यय का अधिकतम केवल 10 प्रतिशतभार ही आता था। यदि सामग्री का हिस्सा 40 प्रतिशत से कम है तो राज्य सरकार को 10 प्रतिशत से भी कम भुगतान पड़ता था।

यह कहना गलत नहीं होगा कि नरेगा में भ्रष्टाचार की कई घटनाएं सामने आईं। कई सरपंचों ने फर्जी मस्टर रोल भी बनाए और सामग्री पर होने वाले खर्च को बड़ा चढ़ा कर दिखाया। उस समय के सरपंचों को ‘बोलेंगे सरपंच’ तक कहा जाने लगा, क्योंकि नरेगा बजट से कई भ्रष्ट सरपंचों ने बोलेंगे गाड़ी खरीद ली थी। भ्रष्टाचार की आशंका को देखते हुए, पारदर्शिता की दृष्टि से यह निर्देश दिए गए थे कि जिन मजदूरों को भुगतान किया जाए उनकी सूची, मय मजदूरी के, विद्यालय अथवा अन्य सार्वजनिक भवन की दीवारों पर लिखवा दी जाए। इससे उन लोगों के नाम भी सामने आए जिन्हें मरने के बाद भी मजदूरी का भुगतान करना दिखा दिया गया।

हालांकि नरेगा में सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान प्रारंभ से ही था, किंतु यह सामान्यतः एक औपचारिकता बनकर रह जाता था। सोशल ऑडिट फोरम की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती थी एवं ठाम सभा में सामान्यतः उपस्थिति बहुत कम होती थी। गरीबी को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान ने पहल की और 2009 में भीलवाड़ा जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में से एक चयनित पंचायत में वास्तविक गहन सोशल ऑडिट कराई गई। इस प्रक्रिया में देश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों और अनेक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी निभाई। लगभग 15 दिनों में इन लोगों ने गांव गांव जाकर सरकारी रिकॉर्ड को सरलीकृत रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और नरेगा की मूल अवधारणा से ग्रामीणों को परिचित कराया। पूरे देश की विभिन्न योजनाओं में नरेगा अकेली ऐसी योजना थी, जिसमें लाखों मजदूरों का विवरण ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध था। मस्टर रोल और वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को जनता के अंजान में आने वाली भाषा में सरल तरीके से इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकत्रित किया और समझाया। इस प्रक्रिया के बाद प्रत्येक पंचायत समिति के मुख्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभावी मंत्री, कलेक्टर, जनता और जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। जब सामग्री में किए गए घोटाले अथवा मजदूरों में दिए गए फर्जी नाम की बात सामने रखी गई तो कुछ स्थानों पर सरपंचों ने आगे बढ़कर गलती स्वीकरी और अतिरिक्त राशि सरकार में जमा करने की बात की ताकि वे आपराधिक कार्यवाही से बच सकें। यह पहला ऐसा उदाहरण था जिसे वास्तविक सोशल

ऑडिट कहा जा सकता था। इस सोशल ऑडिट की सराहना भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने भी की थी। भीलवाड़ा जिले में किए गए इस सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावशीलता को देखते हुए इसे जब अन्य जिलों में भी करने का प्रयास किया गया तो सारे सरपंच लाम बंद हो गए और यह प्रक्रिया आगे बढ़ने से रोक दी गई। यदि सरकार साहस करके इसे अन्य जिलों में भी कर लेती तो संभवतया नरेगा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में बहुत सहायता मिलती।

2005 से 2025 तक लगभग 20 वर्ष तक नरेगा अकुशल श्रमिकों के लिए

;लाइफ लाइन; के रूप में काम करती रही. कोरोना के दौरान, विश्व भर जहां रोजगार के सारे साधन समाप्त हो गए थे, मनरेगा ही संकेत मोचक के रूप में सामने आई।

अब तक नरेगा के अंतर्गत देश में कुल 15.5 करोड़ जाँब कार्ड जारी किए गए हैं तथा 12 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। औसतन एक साल में 200 करोड़ मानव श्रम दिवस सृजित होते हैं। अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, आई एम एफ आदि ने इसे रोजगार सृजन की विश्व की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी योजना माना है। समय-समय पर नरेगा में होने वाले भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए किंतु इसमें और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस बात की भी शिकायतें मिलती थीं कि कई पंचायतें मजदूरों से काम कराने के बजाय वही काम मशीनों से करा लेती थीं। इस प्रकार अनधिकृत रूप से बचाई गई राशि ठेकेदार, सरपंच और भ्रष्ट अधिकारी आपस में बांट लेते थे। हालांकि इस योजना के अंतर्गत एक परिवार को 100 दिन तक काम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार था किंतु वास्तविकता में औसतन 45 दिन प्रति परिवार ही काम मिल पाता था। लगभग 2 प्रतिशत परिवार ही 100 दिन काम कर पाते हैं। अतः काम के दिनों की संख्या नई योजना में 125 दिन करना अर्थ हीन है।

मोदी ने प्रधानमंत्री के कुछ समय बाद 2015 में संसद में नरेगा को यूपीए सरकार की विफलताओं का स्मारक तक कारर दिया था। यह विडंबना ही है कि इसके बावजूद उनकी सरकार इसे 10 वर्षों तक चलाती रही और इसे बंद करने का साहस नहीं उठा पाई। वास्तव में योजना यदि इतनी ही खराब थी तो सरकार ने उसे तत्काल ही बंद क्यों नहीं कर दिया?

सरकार ने हाल ही में अचानक मनरेगा के स्थान पर ‘विकसित भारत – जी राम जी योजना’ (विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन – ग्रामीण) की घोषणा कर दी और इस हेतु बिल संसद में विपक्ष के घोर विरोध के बावजूद ने केवल प्रस्तुत किया अपितु केवल दो दिन की बहस के बाद 18 नवंबर को मध्यरात्रि के बाद संख्या बल के आधार पर इसे पारित भी करा लिया। राष्ट्रपति जी की अनुमति के बाद अब यह कानून भी बन चुका है। इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की विपक्ष की मांग भी नहीं मानी गई।

नए कानून में नरेगा की आत्मा को ही मार दिया गया है। जो योजना मांग आधारित थी उसे केवल एक सामान्य केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में अब चलाया जाएगा। भारत सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितनी धनराशि देनी है। यदि भारत सरकार द्वारा राज्यों को दी जानी वाली राशि से किसी राज्य को खर्च करना है तो उसे अपने साधनों से करना होगा। इस प्रकार यह योजना मांग आधारित से बदलकर आपूर्ति आधारित हो गई है। यह सर्वविदित है कि अधिकांश राज्य भारी कर्ज में डूबे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से अपना काम चला पाते हैं। वह इस योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत खर्च कैसे वहन कर पाएंगे? अब तक राज्यों पर 10 प्रतिशत या उससे कम वित्तीय भार पड़ता था जो बढ़कर अचानक 40 प्रतिशत हो जाएगा। जब राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि वहन नहीं कर पाएंगी तो केंद्र सरकार भी अपना हिस्सा नहीं देगी और इस प्रकार धीरे-धीरे यह योजना बंद हो जाएगी। भारत सरकार ने इस योजना को इस प्रकार का रूप दे दिया है कि वह चल ही न पाए।

जिस प्रकार से योजना का नामकरण सरकार ने किया है उसे देखकर तो लगता है कि श्रष्टों को तोड़ मरोड़ करके योजना के नाम में जैसे-तैसे ‘राम’ शब्द को लाना ही सरकार का उद्देश्य रहा है ताकि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। सरकार को यह समझना होगा कि केवल ‘राम’ का नाम योजना से जोड़ने से कोई योजना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाएगी। कुछ वर्षों पहले सुख-राम; नाम के मंत्री के यहां बिस्तर में करोड़ों रुपए के नोट बरामद हुए थे। गांधी जी की हत्या भी नाथू-राम; ने ही की थी। इसलिए केवल राम के नाम के आधार पर इस योजना का नामकरण करना, सरकार की नीयत में संदेह उत्पन्न करता है।

“विकसित भारत – जी राम जी” राज्यों की स्वायत्तता पर भी प्रहार करती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस योजना के माध्यम से भारत सरकार ने अधिकारों की केंद्रीकरण कर दिया है। इस प्रकार की व्यवस्था भारत के संघीय ढांचे पर गहरा आघात करती है। इसीलिए राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्य तो चाहते हुए भी इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है, किंतु अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। जब इस योजना के अंतर्गत लोगों को का मिलना बंद हो जाएगा और भारत सरकार इसके प्रावधानों को सीमित कर देगी तो जनता में असंतोष बढ़ेगा। जल्दबाजी में इस योजना को लाया गया है और बिना सेलेक्ट कमेटी में भेजे, इसे संसद में 2 दिन में वैसे ही पारित करा लिया गया जैसे कृषि कानून कुछ समय पूर्व सरकार ने पारित करवाए थे। अंततः भारी किसानों के भारी विरोध और 1 वर्ष के लंबे आंदोलन तथा लगभग 700 किसानों की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी थी। जिस जल्दबाजी में, बिना सोच विचार और बिना चर्चा के, ‘जी राम जी’ योजना लाई गई इसे शीघ्र ही सरकार को निरस्त करना पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो,हम यह कहने पर विवश होंगे कि ‘जी राम जी’ को सरकार ने स्वयं नहीं ;जय राम जी; कह दिया है। सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

अरावली पर न्याय का संदेश : संरक्षण जिम्मेदारी का संतुलन



डॉ. अरुण चतुर्वेदी

भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्यावरण, नीति और राजनीति के संगम पर खड़ी है। पिछले दिनों में अरावली को लेकर जिस तरह के आरोप और आशंकाएं फैलाई गई हैं, उन्होंने इस संवेदनशील विषय को तथ्य से अधिक राजनीतिक विमर्श का विषय बना दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अरावली से जुड़े सभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट, लिखित और बाध्यकारी आदेशों के तहत लिए गए हैं और उनका मूल उद्देश्य दीर्घकालिक पारिस्थितिक संरक्षण है।

लगभग दो अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत की जीवनरेखा है। दिल्ली से गुजरात तक

लगभग 650 किलोमीटर में फैली अरावली इंडो-गंगा के मैदानों को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल है और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर बढ़ते प्रभाव को रोकती है। जलवायु, संतुलन, जैव विविधता, भूजल पुनर्भरण और चंबल, साबरमती व लूनी जैसी नदियों के स्रोत के रूप में इसकी भूमिका निर्विवाद है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अरावली को केवल खनन या विकास का विषय न मानकर राष्ट्रीय पारिस्थितिक संपदा के रूप में देखा है।

अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध रहा है और दशकों तक यहाँ खनन गतिविधियाँ चलीं। लेकिन बीते चार दशकों में अत्यधिक और अवैध खनन ने वायु प्रदूषण बढ़ाया, भूजल स्तर गिराया और पारिस्थितिक संतुलन को गहरी चोट पहुँचाई। इसी पुष्टभूमि में 1990 के दशक से पर्यावरण मंत्रालय ने खनन को सीमित करने के प्रयास शुरू किए, 2009 में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया और मई 2024 में नए खनन पट्टों व नवीनीकरण पर रोक लगाई गई।

अरावली विवाद की जड़ लंबे समय तक असंगत परिभाषाएं रही। अलग-अलग राज्यों और संस्थानों द्वारा अलग मानक अपनाए जाने से न केवल भ्रम फैला, बल्कि अवैध खनन को भी बढ़ावा मिला। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय

वन सर्वेक्षण, राज्य वन विभागों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और विशेषज्ञों को शामिल कर संयुक्त समिति गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर 20 नवंबर 2025 को अंतिम निर्णय दिया गया।

कुछ राजनीतिक बयानों में यह आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने अरावली को 100 मीटर में समेट दिया। यह आरोप न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास भी है। वास्तविकता यह है कि 100 मीटर की सीमा कोई नई खोज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2005 को 100 मीटर से अधिक ऊँचाई को हिल मानने का मानक तय किया था, जिसे वर्षों तक कांग्रेस सरकारों ने भी लागू रखा।

वर्तमान निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाली पहाड़ियाँ और उनसे 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी लैंडफॉर्म्स एक संरक्षित श्रृंखला माने जाएँ। इस 500 मीटर ज़ोन में आने वाले सभी भू आकृतिक ढांचे (उनकी ऊँचाई या ढलान चाहे जो भी हो) खनन से पूरी तरह बाहर रहेंगे। इसलिए यह कहना कि 100 मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में खनन खोल दिया गया है, सरासर भ्रामक है।

अरावली का 98 प्रतिशत भाग सुरक्षित है। यह नितांत तथ्यहीन है कि 90 प्रतिशत अरावली समाप्त हो गई।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यों की कसौटी पर नितांत तथ्यहीन हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके कार्यकाल में अरावली के लिए दोस संरक्षण मॉडल विकसित किया जा सकता था, तब कोई निर्णायक पहल नहीं हुई। आज जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक सख्त, वैज्ञानिक और

814वां उर्स : सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह पर प्रधानमंत्री मोदी की चादर पेश



केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा को पेश की।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्किट हाउस में मीडिया से रुबरू भी हुए। उन्होंने कहा कि चादर पीएम, सरकार हम सभी की तरफ से है। पीएम के संदेश पर बोले कि मैं खुद आया हूं, मैं जो बोलूंगा वो ही संदेश होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, भागीरथ चौधरी और मंत्री सुरेश रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि महफिल खाने में पहुंचे। उन्होंने चादर पेश कर देश में अमन-चैन-शांति और भाईचारा बना रहे की दुआ मांगी। दरगाह दीवान के पुत्र नसरूद्दीन चिश्ती की ओर से मंत्री दोरान सीटी स्कैन से लेकर कई टेस्ट किए गए। जांच में उसके सेरेब्रल एडिमा पाई गई। इसके बाद जांच में

जोधपुर एम्स में पांच साल के बच्चे के ब्रेन डेड होने पर परिवार ने ऑर्गन डोनेट किये

■ पांच साल के मासूम के अंगदान से मिलेगी दो लोगों को नई जिंदगी, किडनी और लिवर दोनों डोनेट किए

स्टेट्स एस्प्लिटक्स और सेंट्रल डायबिटीज एनसीपीडस हुआ। दिमाग

में बार बार दौर पड़ने से भोमाराम ब्रेन डेड हो गया। इसके बाद परिवार को ऑर्गन डोनेट करने के बारे में बताया गया। इस पर परिवजन सहमत हुए और उसके बाद सोमवार सुबह ऑर्गन डोनेशन करने के बाद बाँडी परिवजनों को सुपुर्द की गई। उसका एक लिवर फ्लाइट से आईएलबीएस दिल्ली भेजा गया, जबकि उसकी दो किडनी जोधपुर एम्स में ही एडमिट मरीज को

लगाई गई। एम्स के अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि इस अंगदान से दो लोगों को नई जिंदगी मिल सकेगी। ट्रांसप्लांट के नोटल अधिकारी दो शिवचरण ने बताया कि ऑर्गन डोनेट करने के बाद पांच से छह घंटे में लगाना जरूरी होता है, इसलिए लिवर को फ्लाइट के जरिए दिल्ली भेजा गया।

राशिफल मंगलवार 23 दिसम्बर, 2025

पौष मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, श्रवण नक्षत्र बुधवार प्रातः 6:08 तक, व्याघात योग सायं 4:30 तक, गर करण दिन 12:13 तक, चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-धनु, मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरू-मिथुन, शुक्र-धनु, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।
आज रवियोग सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। भद्रा रात्रि 12:42 से आरम्भ होगी। आज अंगारक चतुर्थी, विनायक चतुर्थी है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:51 से 11:08 तक, लाभ-अमृत 11:08 से 1:43 तक, शुभ 3:00 से 4:18 तक।
राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 7:17, सूर्यास्त 5:35 तक

	मेघ व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुसमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।
	वृष नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा।
	मिथुन चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।
	कर्क परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मौंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

	सिंह विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।
	कन्या व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वातां सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।
	तुला घर-परिवार में अतिथियों का आमनन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

	धनु आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। परिवार में उसव जैसा माहौल रहेगा।
	मकर मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। पारिवारिक व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रहे।
	कुंभ घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज अंगर्गत कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
	मीन अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

बजरी माफिया से सांठगांठ पर 1 1 पुलिस निरीक्षकों पर गाज गिरी

पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा ने प्रदेशभर में किया डिकॉय ऑपरेशन

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। प्रदेश में बजरी माफियाओं से सांठगांठ और गंभीर लापरवाही रखने वाले 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस सेंगाथिर के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा द्वारा डिकॉय ऑपरेशन करने के बाद यह कार्रवाई हुई।

प्रदेशभर में चलाए गए डिकॉय ऑपरेशन के बाद कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही और अवैध बजरी खनन में संलिप्तता पाए जाने पर गाज गिरी है। इस कार्रवाई में पांच पुलिस निरीक्षकों को तत्काल निलंबित किया गया है, जबकि छह अन्य को लाइन हाजिर किया

■ **पांच पुलिस निरीक्षक निलंबित, अन्य 6 को लाइन हाजिर किया गया है।**

एडीजी सेंगाथिर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गठित 11 विशेष टीमों ने 18 और 19 दिसंबर को राज्य के विभिन्न जिलों में गुप्त तरीके से डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया। इन टीमों ने आम नागरिक बनकर पुलिस थानों की कार्यप्रणाली, नाकाबंदी और गश्त व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सामने

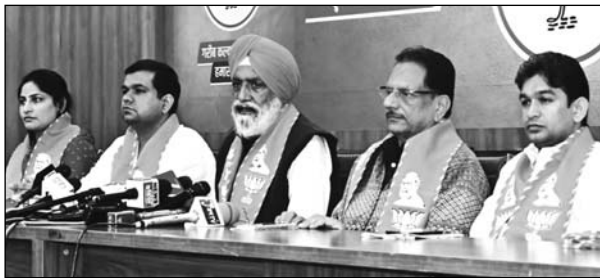
आया कि कई थानों में न केवल बजरी के अवैध परिवहन को नजरअंदाज किया जा रहा था,बल्कि ड्यूटी के प्रति भी भारी लापरवाही बरती जा रही थी।

जांच में दोषी पाए जाने पर 21 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय ने सख्त कदम उठाते हुए जयपुर दक्षिण जिले के शिवदासपुरा, टोंक के पीपलू व बरीनी, अजमेर के पीसांगन और धौलपुर के कोतवाली थाना अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही भीलवाड़ा के थाना गुलाबपुरा, कोटा शहर के कुन्हाडी व नात्ता, दोसा के लालसोट, चित्तौड़गढ़ के गंगारार और जोधपुर पश्चिम के लूणी थाना अधिकारियों को

लाइन हाजिर किया गया है। इन सभी के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

बजरी माफिया के मददगारों के लिए विभाग में जगह नहीं : पुलिस मुख्यालय ने कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण में किसी भी पुलिसकर्मी की मिलीभगत या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे दोषी कार्मिकों के विरुद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। ऑपरेशन में दोषी मिले 11 थानों के 15 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पीएचक्यू से आईजी जयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर को निर्देश जारी किए गए हैं।

इससे पहले नवंबर माह में भी सतर्कता शाखा ने एक व्यापक अभियान चलाया था। उस दौरान जीरो एफआईआर दर्ज न करने, परिवारियों से दुर्व्यवहार, साइबर क्राइम की शिकायतों पर हिलाई, एसपी ऑफिस में प्राप्त परिवारों में परिवार अनुभाग की कार्यप्रणाली, थाना अधिकारियों की गश्त प्रणाली एवं कार्यशैली और महिला डेस्क पर आने वाली महिलाओं के साथ संवेदनहीन व्यवहार जैसे बिंदुओं पर डिकॉय ऑपरेशन किया गया था।



भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं ‘वीर बाल दिवस’ कार्यक्रम प्रदेश समन्वयक सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने सोमवार को प्रेस वार्ता की।

के उद्देश्य से प्रदेशभर में मंडल से लेकर जिला स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। ‘वीर बाल दिवस’ कार्यक्रम प्रदेश समन्वयक सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने बताया कि वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, जिला स्तरीय बौद्धिक संगोष्ठियां, स्कूलों एवं कॉलेजों में विचार संगोष्ठियां तथा भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेगी। इसके साथ ही 26 दिसंबर को राजकीय विद्यालयों में एक घंटे के विशेष सत्र के दौरान बच्चों को वीरता और शहादत की प्रेरणादायक कहानियां सुनाई जाएंगी।

उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता मंडल स्तर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन करेंगे तथा साहित्यकारों की शहाबाद व किशनगंज ब्लाक की सहरीया जनजाति बहुल 100 से अधिक आबादी की 31 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई। इसके तहत लगभग 11 करोड़ की लागत से 22 किमी. सड़क निर्माण कर 11 बसावटों को सड़कों से जोड़ने का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगतिरत है।

गांवों को आत्मनिर्भर बनाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 2 5 साल पूर्ण हुए

जयपुर (कासं)। स्वतंत्रता के दशकों बाद तक भारत के ग्रामीण क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। इन सुविधाओं तक पहुंचने के लिए एक मार्ग की जरूरत थी। इसी जरूरत को समझते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में भारत के असंबद्ध गांवों को सड़क से जोड़ने की मजबूत नींव रखी। जिसके तहत सामान्य क्षेत्र की 500 से अधिक एवं मरुस्थलीय तथा आक्विफरी क्षेत्र की 250 से अधिक आबादी की बसावटों को सर्वकालिक पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा आगे चलकर

- **प्रदेश में 75 हजार से अधिक किलोमीटर सड़कें तथा 68 गुल बनाकर 15983 बसावटों को जोड़ा गया**
- **केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मेड़ता में 2089 करोड़ रुपये लागत की 1216 पीएमजीएसवाई सड़कों की सौगात देंगे**

आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय कृषि, कृषक सौगात देंगे। जिनकी अनुमानित लम्बाई 3219 किमी. व लागत लगभग 2 हजार 89.37 करोड़ होगी।

गौरतलब है कि चौथे चरण में 1638 बसावटों को सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश

में लगभग 12086 करोड़ रूपये की लागत से 49730 किमी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण कर 15983 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ा गया। साथ ही 14043 किमी. सड़कों के चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया गया तथा 26 पुलों का निर्माण करवाया गया।

जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, चर्यानित “शू रूट्स और ग्रामीण सड़क नेटवर्क” को अधिक मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सिर्फ नयी सड़कों का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि मौजूदा सड़कों के नेटवर्क को और अधिक

मजबूत करना भी आवश्यक है। योजना के दूसरे चरण में प्रदेश में 1103 करोड़ रुपये की लागत से 3468 किमी. लम्बाई की 401 सड़कों का चौड़ाईकरण-सुदृढ़ीकरण कार्य करवाया गया तथा 6 पुलों का निर्माण करवाया। योजना के तीसरे चरण में भी मौजूदा मार्गों व ग्रामीण संपर्क मार्गों को उन्नत किया गया ताकि बसावटों से कृषि बाजारों, कॉलेजों, अस्पतालों, अन्य किसान संबंधित उद्यमों तक सुगम एवं त्वरित कनेक्टिविटी स्थापित की जा सके। अब तक प्रदेश में 4060 करोड़ रुपये की लागत से 8549 किमी. की 903 सड़कों का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाया गया तथा 36 पुलों

एम.एन.आई.टी. में प्रस्तावित ट्रेड फेयर पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एमएनआईटी परिसर में अगले माह प्रस्तावित सोलर ट्रेड फेयर को लेकर शिक्षा मंत्रालय, एमएनआईटी निदेशक, राजस्थान सोलर एसोसिएशन, मुख्य सचिव और सीपीजे सहित अन्य को जवाब पेश करने के लिए 13 जनवरी तक का समय दिया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश संयुक्त अभिवाक संघ की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

जनहित याचिका में अभिवक्ता विनोद कुमार वैष्णव ने अदालत को बताया कि जेएलएन मार्ग स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अगली 16 जनवरी से तीन दिवसीय ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सोलर क्षेत्र से जुड़ी प्रदेश की दर्जनों निर्माता और सेवा प्रदाता कंपनियां भाग लेंगी। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत विद्यार्थियों को शांत और

- **बताया जा रहा है कि 16 जनवरी से प्रस्तावित 3 दिवसीय इस ट्रेड फेयर में सोलर क्षेत्र से जुड़ी दर्जनों निर्माता और सेवा कंपनियां भाग लेंगी**
- **याचिका में कहा गया कि, “संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत विद्यार्थियों को शांत और शुद्ध शैक्षणिक वातावरण का अधिकार है। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में व्यावसायिक आयोजन नहीं किया जाना चाहिए।”**

शुद्ध शैक्षणिक वातावरण का अधिकार है। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में व्यावसायिक आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि एमएनआईटी जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान के परिसर में इस तरह के व्यापारिक मेलों का आयोजन न केवल शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करता है, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन और गरिमा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि परिसर में बने हॉस्टल में बड़ी संख्या में विद्यार्थी रहते

है और बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को लेकर भी कड़ी सुरक्षा के प्रावधान हैं। ऐसे में बिना जांच पड़ताल कंपनियों से जुड़े लोगों को यहां प्रवेश देना उचित नहीं है। ऐसे में इस प्रस्तावित ट्रेड फेयर के आयोजन को रोका जाए। याचिका में पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी भारत व्यास व अन्य वकील उपस्थित हुए और उन्होंने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने याचिका की सुनवाई 13 जनवरी को रखते हुए पक्षकारों को जवाब पेश करने को कहा है।

रिलायंस ज्वैल्स की “ड्रीम डायमण्ड सेल” शुरू

मुंबई। रिलायन्स ज्वैल्स अपनी “ड्रीम डायमण्ड सेल” फिर से लेकर आए है, जिसके तहत उपभोक्ता आकर्षक एवं लुभावने तरीके से इस सीजन का ख़र्चन मना सकेंगे। यह सेल देश भर में 145 से अधिक रिलायन्स ज्वैल्स स्टोर्स पर उपलब्ध है। आगामी 27 जनवरी 2026 तक चलने वाली यह सेल ऐसे समय में लाई जा रही है, जब लोग साल के अंत में उपहार खरीदते हैं, त्योहारों की खरीददारी करते हैं या किसी यादगार के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। इस साल की ड्रीम डायमण्ड सेल, हर किसी के लिए हीरो की खरीद को सुलभ बनाएगी। ग्राहकों को 25 हजार रु. के हीरो की हर खरीद पर 0.25 ग्राम का गोल्ड कॉइन मिलेगा। इस सीजन की सेल हीरा और सोना एक साथ खरीदने का अनूठा मौका मिलेगा। सेल के दौरान 75 हजार रु. की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर मैकिंग चार्ज पर फ्लैट 20



फीसदी छूट मिलेगी। रिलायन्स ज्वैल्स स्टोर्स में ग्राहक, रोजमर्रा के लिए डायमण्ड ज्वेलरी जैसे ईयररिंग, रिंग, चेन या स्टेटेमेंट स्टायल जैसे चोकर और ब्राइडल डिजाइनों की खरीददारी कर सकेंगे।

“जयपुर ज्वैलरी शो” कला-विरासत और परंपरा का उत्सव : प्रेमचंद बैरवा जे.ई.सी.सी. में जे.जे.एस. संपन्न हुआ, बीते 4 दिनों में करीब 4 6 हजार विजिटर्स ने की शिरकत



जयपुर ज्वैलरी शो के समापन समारोह में सोमवार को उत्कृष्ट बूथ डिजाइन और ज्वैलरी प्रस्तुति के अवार्ड देकर प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

जयपुर (कासं)। जयपुर आभूषण की दुनिया में एक विशिष्ट स्थान रखता है और जयपुर ज्वैलरी शो इस शहर की समृद्ध विरासत, परंपरा और कला का उत्सव है। यह बात राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर ज्वैलरी शो 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आभूषण उद्योग आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार प्रातिशील नीतियों और ईए ऑफ ड्रॉप बिजनेस के जरिए इस उद्योग को सहयोग करने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

जेजेएस वार्ड्स चेयरमैन दिनेश खटोरिया ने कहा कि अपने शुरुआती

- **18 से 21 दिसंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा आगामी संस्करण**

वर्षों में मात्र 67 बूथों से शुरू होकर आज 1227 बूथों तक पहुंचना इस शो की उल्लेखनीय विकास यात्रा को दर्शाता है। आज यह एजीबिशन देश की सबसे बड़ा बी2बी और बी2सी प्लेटफॉर्म बन चुकी है।

जेजेएस के मानद सचिव राजीव जैन ने बेस्ट बूथ अवॉर्ड्स की घोषणा की। उत्कृष्ट बूथ डिजाइन और ज्वेलरी प्रस्तुति के लिए 18 वर्ग मीटर से ऊपर बेस्ट बूथ ज्वेलरी श्रेणी में विजेताओं में पहला स्थान बिरछीचंद घनश्याम दास ने जीता। दूसरे स्थान पर

मोहनलाल नारायणदास ज्वैलर्स रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वैलरी (आईआईजीसी) को बेस्ट इंस्टीट्यूट अवॉर्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने शो के अगले संस्करण की तारीखों की भी घोषणा की, जो 18 से 21 दिसंबर, 2026 तक आयोजित होगा। जैन ने बताया कि इस वर्ष शो में 46 हजार से ज्यादा विजिटर्स आए, जिनमें से 15 हजार बाहर के शहरों से थे।

जेजेएस के संयुक्त सचिव और प्रवक्ता अजय काला ने समापन समारोह का संचालन किया। उन्होंने कहा कि इस बार जेजेएस व्यवसाय के साथ-साथ प्रबंधन की दृष्टि से भी व्यापक और उपयोगी शो रहा। उन्होंने शो की सफलता के लिए सभी प्रदर्शकों, चित्रेताओं और आगंतुकों का आभार जताया।

वीकेंड के बाद भी सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले में रौनक बरकरार



जयपुर । सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला-2025 में वीकेंड के बाद भी उत्साह और चहल-पहल कम नहीं हुई। सोमवार को मेले के पाँचवें दिन सामान्य कार्यदिवस होने के बावजूद मेला परिसर में भीड़ देखने को मिली। शिल्प, हस्तकला और स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि ने मेले को एक जीवंत उत्सव का रूप दे दिया।

परिवारों के साथ आए दर्शकों ने विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना की और स्थानीय स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) महिलाओं के उत्पादों की जमकर खरीदारी की। इसी क्रम में टाइनी टॉट्स इंग्लिश स्कूल के स्कूली बच्चों ने भी मेले का भ्रमण किया।

<

